



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 1985/भाद्र 11, 1907

No. 392]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 1985/BHADRA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 गिनम्बर, 1985

सं. 286/85 सीमाशुल्क

सा. का. नि. 704. (अ) केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 9 ख की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते, हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ (बाउन्टी दत्त वस्तु की पहचान, उस पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा श्रुति का अवधारण) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 अभिप्रेत है;

(ख) "अभिहित प्राधिकारी" से नियम 3 के अधीन अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "घरेलू उद्योग" से उसी या वैसी ही वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन में या उससे संबंधित किसी क्रियाकलाप में लगे हुए समस्त घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक पर्याप्त भाग तब के सिवाय बनाता है जब ऐसे उत्पादक अभिकषित बाउन्टी दत्त या सहायता प्राप्त वस्तु के निर्यातकर्ताओं या आयातकर्ताओं के नातेदार हैं या वे स्वयं उसके आयातकर्ता हैं। ऐसी दशा में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा :

परन्तु इन नियमों के नियम 17 के उपनियम (3) में निविष्ट परिस्थितियों में, प्रस्तुत वस्तु के संबंध में किसी ह्रासकरता राज्यक्षेत्र को दो या अधिक प्रतियोगी बाजारों में विभाजित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादकों को एक प्रलग उद्योग समझा जाएगा यदि :

(i) ऐसे किसी बाजार के भीतर उत्पादक प्रस्तुत वस्तु का अपने सभी या लगभग सभी उत्पादन का उस बाजार में विक्रय करते हैं; और

(ii) उस बाजार माँग की, राज्यक्षेत्र में अन्यत्र अवस्थित प्रस्तुत वस्तु के उत्पादकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं की जाती है;

- (घ) "सहायकी और प्रतिरोधी उद्योगों के संबंध में टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार" से तारीख 12 अप्रैल, 1979 के टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार के अनुच्छेद 8, 16 और 23 के निर्वचन और लागू किए जाने संबंधी करार अभिप्रेत है;
- (ङ) "हितवद्ध पक्षकार" से ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिस पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है और जो इन नियमों के अधीन अन्वेषण में हितवद्ध है;
- (च) "हितवद्ध हस्ताक्षरकर्ता" से ऐसा हस्ताक्षरकर्ता अभिप्रेत है जिस पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है और जो इन नियमों के अधीन अन्वेषण में हितवद्ध है;
- (छ) "हस्ताक्षरकर्ता" से ऐसा देश या राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार के अनुच्छेद 6, 16 और 23 के निर्वचन और लागू किए जाने संबंधी करार का पक्षकार है या जिसको उगम अंगीकार किया है;
- (ज) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव को या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह सरकार ठीक समझे, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार उस अभिहित अधिकारी को ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएँ और ऐसी अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करा सकेगी जो वह ठीक समझे।

4. अभिहित प्राधिकारी के कर्तव्य—(1) इन नियमों के अनुसार अभिहित प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह—

- (क) किसी वस्तु की अभिधायित बाउंटो या सहायकी की विश्वमानता, मात्रा और प्रभाव के बारे में अन्वेषण करे;
- (ख) किसी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के लिए दायी वस्तुओं की पहचान करे; और
- (ग) ऐसी वस्तुओं के संबंध में सहायकी या बाउंटो की प्रकृति और रकम के बारे में केन्द्रीय सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करे;

(2) यदि अभिहित प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्वेषण करने के पश्चात् किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किसी देश या राज्यक्षेत्र ने किसी ऐसी वस्तु पर जिसको अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) लागू होती है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई बाउंटो या सहायकी संदत्त या प्रदत्त करते हैं तो वह केन्द्रीय सरकार को उक्त उपधारा में उपबंधित मात्रा तक या रीति में, यथास्थिति, किसी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के अन्तिम या अन्यथा अधिरोपण के लिए सिफारिश कर सकेगा।

परन्तु ऐसे देशों या राज्यक्षेत्रों की दशा में जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं यथास्थिति, कोई ऐसा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक अभिहित प्राधिकारी ने इन नियमों के अनुसार कोई यह और निष्कर्ष दे दिया हो कि ऐसी वस्तु का भारत में आयात किया जाता भारत में स्थापित किसी उद्योग का तात्त्विक क्षति पहुँचाता है या उसका उत्पन्न करता है या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में तात्त्विक प्रतिरोध उत्पन्न करता है।

5. उद्भव के देश के बारे में विनिश्चय यदि किसी वस्तुओं का भारत में उद्भव के देश से सीधे आयात नहीं किया जाता है किन्तु किसी मध्यवर्ती देश से आयात किया जाता है तो इन नियमों के उपबंध

पूर्णतया लागू होंगे और कोई ऐसा मुख्यद्वार सहाय की और प्रतिरोधी उद्योगों के संबंध में टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार के प्रयोजनों के लिए उद्भव के देश और आयातकर्ता देश के बीच किया गया समझौता जाएगा।

6. अन्वेषण का शुरु किया जाना,—(1) अभिहित प्राधिकारी प्रभावित घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से किसी निश्चित अनुरोध की प्राप्ति पर ही प्रस्तावनायनया कोई अन्वेषण शुरू करेगा।

(2) अभिहित प्राधिकारी कोई अन्वेषण शुरू करने से पहले अपना यह संनाधान करेगा कि उसके पास—

- (क) बाउंटो या सहायकी की विश्वमानता का और उसकी मात्रा का,
- (ख) टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार के अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट मात्रा तक, जहाँ लागू हो, क्षति का जैसा कि सहायकी और प्रतिरोधी उद्योगों के संबंध में टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार में निर्वचन किया जाएगा; और
- (ग) जहाँ लागू हो ऐसे आयातों और अभिकषित क्षति के बीच किसी आकस्मिक संबंध का पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य है।

(3) उपनिर्णय (1) में किसी बात के होते हुए भी, अभिहित प्राधिकारी कोई अन्वेषण स्वरेरणा से शुरू कर सकेगा यदि उसका सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन नियुक्त सीमाशुल्क कलक्टर से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी से यह संनाधान हो जाता है कि बाउंटो या सहायकी की ओर जहाँ लागू हो क्षति की विश्वमानता के बारे में पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य विश्वमान है।

7. अन्वेषण की अधिसूचना अभिहित प्राधिकारी कोई अन्वेषण शुरू करने का विनिश्चय करने के पश्चात् संबंधित निर्यातकर्ता देशों की सरकारों को ऐसी वस्तुओं के नाम सूचीबद्ध करेगा जिनके बारे में ऐसा अन्वेषण किए जाने की प्रस्तावना है।

8. निरीक्षण प्रतिनिधित्व करने का अवसर—अभिहित प्राधिकारी हितवद्ध पक्षकारों के और हितवद्ध हस्ताक्षरकर्ताओं के सम्पर्क रूप से पाधिकृत प्रतिनिधियों को—

- (क) उसके अनुरोध पर किसी ऐसी भुगतान जानकारी का जो उसके अन्वेषण में प्रयोग की है और जो गोपनीय नहीं है निरीक्षण करने का यकिनयुक्त अवसर देगा; और

(ख) निश्चित में और पर्याप्त हेतुक दर्शन किए जाने पर मौखिक रूप से उपजे विचार प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

9. गोपनीय जानकारी—(1) किसी अन्वेषण के अनुक्रम में किसी पक्षकार द्वारा अभिहित प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर दी गई कोई जानकारी उसकी गोपनीयता के बारे में अभिहित प्राधिकारी का संनाधान हो जाने पर उक्त द्वारा गोपनीय मार्गी जागी और अभिहित प्राधिकारी द्वारा कोई ऐसी जानकारी ऐसे पक्षकार के आँ ऐसी जानकारी देता है विनिर्दिष्ट प्राधिकार के बिना अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) अभिहित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसके प्रयोगनीय संक्षेप देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि ऐसी जानकारी देने वाले किसी पक्षकार की राय में ऐसी जानकारी का संक्षेप नहीं बनाया जा सकता है तो ऐसा पक्षकार अभिहित प्राधिकारी को ऐसे कारणों का कथन प्रस्तुत कर सकेगा कि उसका संक्षेप संभव नहीं है।

(3) उपनिर्णय (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि अभिहित प्राधिकारी का यह संनाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है और यदि गोपनीयता के बारे में अनुरोध करने वाला पक्षकार उसके लिए जो कारण है उन्हें प्रकट करने के लिए राजासद नहीं है तो अभिहित प्राधिकारी ऐसी जानकारी की अवहेलना सकेगा।

10. अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के राज्यक्षेत्र में अन्वेषण—(1) अभिहित प्राधिकारी अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के राज्यक्षेत्रों में अन्वेषण कर सकेगा यदि किसी मामले की परिस्थितियों में ऐसा आवश्यक हो, परन्तु यह तब जब कि अभिहित प्राधिकारी ऐसे हस्ताक्षरकर्ताओं को पहले ही से अधिसूचित कर देता है और ऐसे हस्ताक्षरकर्ताओं अन्वेषण के बारे में आशय नहीं करते हैं।

(2) अभिहित प्राधिकारी किसी वाणिज्यिक संगठन के परिणामों में भी अन्वेषण कर सकेगा और उसके अभिलेखों की परीक्षा कर सकेगा, यदि ऐसा संगठन महत्व हो जाता है और यदि हस्ताक्षरकर्ता को, जिसके राज्यक्षेत्र में उक्त वाणिज्यिक संगठन स्थित है, यह अधिसूचित कर दिया जाता है और उसने ऐसे अन्वेषण के लिए जाने के बारे में कोई आशय नहीं किया है।

11. सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर निष्कर्ष—यदि कोई हितवद् पक्षकार या हस्ताक्षरकर्ता, अभिहित प्राधिकारी को युक्तियुक्त अवधि के भीतर पहुँच करने से इकार करता है या उसको अन्यथा आवश्यक जानकारी नहीं देता है या उसके अन्वेषण में अडचन डालता है तो अभिहित प्राधिकारी अपने को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा जो वह परिस्थितियों के अर्थात् ठीक समझे।

12. प्रारम्भिक निष्कर्ष—अभिहित प्राधिकारी, अन्वेषण करने के लिए, सीधे कार्यवाही करेगा और समुचित मामलों में प्रारम्भिक निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

13. अनन्तिम शुल्क—केन्द्रीय सरकार किसी भी समय किसी वस्तु पर, यथास्थिति, अनन्तिम शुल्क या अनिश्चित शुल्क अधिरोपित कर सकेगी, यदि अभिहित प्राधिकारी, उसको उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर, प्रारम्भिक निष्कर्ष करता है कि ऐसी वस्तुओं के संबंध में किसी बाउंटी या सहायकी का उपबंध किया गया है जो अन्वेषण की विषयवस्तु है।

परन्तु किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में जिसको धारा 9ख लागू होती है, यथास्थिति कोई भी अनन्तिम शुल्क या अनिश्चित शुल्क तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक अभिहित प्राधिकारी उसको उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर किसी ऐसे और निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना है कि इस बात का पर्याप्त साध्य है कि ऐसी वस्तु का आयात किया जाता, टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार के अनुच्छेद 6 के अर्थ के अन्तर्गत भारत में स्थापित किसी उद्योग को तात्त्विक क्षति पहुँचा रहा है या उसका खतरा उत्पन्न कर रहा है या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में तात्त्विक गतिरोध उत्पन्न कर रहा है जैसा कि सहायकी और प्रतिरोधी उपकरणों के संबंध में टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार द्वारा निर्वाचित किया जाए और अनन्तिम शुल्क, अन्वेषण की अवधि के दौरान पहुँचाई गई क्षति को रोकने के लिए आवश्यक है।

14. अन्वेषण की समाप्ति या निलम्बन—(1) अभिहित प्राधिकारी अपने विवेकानुसार, किसी अन्वेषण को निलम्बित या समाप्त कर सकेगा—

(क) यदि वह ऐसे प्रभावित वस्तु उद्योग की ओर से जिसके अनुरोध पर अन्वेषण शुरू किया गया था, ऐसा करने के लिए लिखित में अनुरोध प्राप्त करता है, या

(ख) जब किसी अन्वेषण के अनुक्रम में, अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि बाउंटी या सहायकी का, या जहाँ लागू हो, क्षति का पर्याप्त साध्य नहीं है जिससे कि अन्वेषण बालू रखा जाना न्यायोचित ठहराया जा सके।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अभिहित प्राधिकारी किसी अन्वेषण का निलम्बित या समाप्त कर सकेगा यदि —

(क) निर्यातकर्ता हस्ताक्षरकर्ता की सरकार —

(i) लिखित में इस आशय का बचनबद्ध करती है कि यह बाउंटी या सहायकी को वापस ले लेगी; या

(ii) ऐसे देशों की दशा में जिनको अधिनियम की धारा 9ख लागू होती है, बाउंटी या सहायकी की मात्रा को युक्तियुक्त सीमाओं के भीतर सीमित करने का या ऐसी बाउंटियों या सहायकी के प्रभाव को बेकार करने के लिए अन्य उपयुक्त उपाय करने का बचनबद्ध करती है, परन्तु यह तब जब कि अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सहायकी का हानिकारक प्रभाव कम हो गया है; या

(ख) ऐसे देशों की दशा में जिनका अधिनियम की धारा 9ख लागू होती है, संबंधित निर्यातकर्ता अपनी कीमतों का पुनरीक्षण करने के लिए सहमत हो जाते हैं और अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सहायकी का हानिकारक प्रभाव कम हो गया है।

परन्तु खंड (ख) के परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि उससे उच्चतर नहीं होगी जो बाउंटी या सहायकी की रकम को कम करने के लिए आवश्यक है।

(3) उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन कीमत में वृद्धि के संबंध में कोई बचनबद्ध किसी विदेशी निर्यातकर्ता से तब तक प्रतिगृहीत नहीं किया जाएगा जब तक अभिहित प्राधिकारी ने, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कोई अन्वेषण शुरू करने के पश्चात्, ऐसे पुनरीक्षण के लिए निर्यातकर्ता हस्ताक्षरकर्ता की सरकार से सहमति प्राप्त नहीं करती है।

परन्तु विदेशी निर्यातकर्ताओं द्वारा प्रस्थापित कोई ऐसा बचनबद्ध अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रतिगृहीत नहीं किया जाएगा यदि वह किसी अन्य कारण से उसके प्रतिग्रहण को असाध्य या अप्रतिग्रहणीय समझता है।

(4) जहां अभिहित प्राधिकारी ने उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन कोई बचनबद्ध प्रतिगृहीत किया है वहां वह किसी ऐसे हस्ताक्षरकर्ता या निर्यातकर्ता से, जिससे ऐसा बचनबद्ध प्रतिगृहीत किया गया है, समय-समय पर, बचनबद्ध के पूरा किए जाने से सुसंगत जानकारी देने और सुसंगत आकड़े या सत्यापन अनुज्ञात करने का अनुरोध कर सकेगा।

परन्तु किसी बचनबद्ध के किसी प्रतिग्रहण की दशा में अभिहित प्राधिकारी अपने को उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर यथास्थिति अनन्तिम शुल्क या अनिश्चित शुल्क अधिरोपित कर सकेगा।

(5) अभिहित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या प्रश्नगत वस्तु के निर्यातकर्ताओं या आयातकर्ताओं से या किसी अन्य हितवद् व्यक्ति से प्राप्त किसी अनुरोध के आधार पर, किसी भी समय, पहले ही दिए गए किसी बचनबद्ध को चालू रखे जाने की प्रावण्यकता का पुनरीक्षण करेगा।

15. अभिहित प्राधिकारी किसी अन्वेषण के शुरू किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार प्रसाधारण मामलों में मंजूर करें, निम्नलिखित के बारे में अंतिम निष्कर्ष देगा कि —

(क) अन्वेषण के अधीन वस्तु की बाबत बाउंटी या सहायकी मंजूर की गई है या नहीं और ऐसी बाउंटी या सहायकी की मात्रा, और

(ख) ऐसे देशों की दशा में, जिनको अधिनियम की धारा 9ख लागू होती है, क्या उक्त वस्तुओं का भारत में आयात किया जाना, भारत में स्थापित किसी उद्योग को तात्त्विक क्षति पहुँचाता है या उसका खतरा उत्पन्न करता है या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में तात्त्विक गतिरोध उत्पन्न करता है।

16. बाउंटी या सहायकी का अवधारण :—किमी वैसे ही उत्पाद पर, यदि वह घरेलू उपयोग के लिए पूर्वनिर्दिष्ट है तो, लगने वाले शुल्क या कर से किसी निर्यात की गई वस्तु की किसी छूट को या ऐसी रकमों तक, जो उन रकमों से अधिक नहीं होंगी जो प्राविष्ट हो गई हैं, ऐसे शुल्क या कर की छूट को, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सहायकी नहीं समझी जाएगी और "सहायकी" शब्द के अंतर्गत कोई ऐसी सहायकी है किन्तु वह किसी ऐसी सहायका तक सामिल नहीं है जो सहायकी या प्रतिरोधी उपायों के संबंध में टैरिफ और व्यापार संबंधों साधारण करार के उपाबंध में इस प्रकार उल्लिखित है।

17. क्षति का अवधारण :—(1) अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित देशों या राज्यक्षेत्र की वशा में, यथास्थिति, कोई शुल्क या अतिरिक्त शुल्क अधिनियम की धारा 9 के अधीन तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक अभिहित प्राधिकारी ऐसा कोई और निष्कर्ष नहीं देता है कि ऐसा वस्तु का भारत में आयात किया जाना, भारत में स्थापित किमी उद्योग को तात्त्विक क्षति पहुंचाता है या उसका खतरा उत्पन्न करता है या भारत में किसी उद्योग का स्थापना में तात्त्विक गतिरोध उत्पन्न करता है।

(2) जब क्षति का कोई निष्कर्ष उपनियम (3) के अधीन दिया जाता है तब ऐसे निष्कर्ष में ऐसे तथ्यों की परीक्षा अंतर्बलित होगी जिन्हें अभिहित प्राधिकारी परिस्थितियों के अधीन सुसंगत समझे, जिनके अंतर्गत बाउंटी वस्तु या सहायता प्राप्त आयातों की मात्रा और वैसे ही उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का पारिणामिक प्रभाव है।

(3) अभिहित प्राधिकारी, अवसाधारण मामलों में, क्षति की विद्यमानता के बारे में इस बात के ह्रांसे हुए भी निष्कर्ष दे सकेगा कि घरेलू उद्योग के पर्याप्त भाग को क्षति नहीं हुई है यदि—

- (i) बाउंटी वस्तु या सहायता प्राप्त आयातों का किसी एकल बाजार में संकेन्द्रण है; और
- (ii) बाउंटी वस्तु या सहायता प्राप्त आयात, ऐसे बाजार के भीतर सभी या लगभग सभी उत्पादन के उत्पादकों की क्षति पहुंचा रहे हैं।

18. अंतिम निष्कर्ष का परिणाम :—(1) अभिहित प्राधिकारी अपना अन्वेषण पूरा कर लेने पर, केन्द्रीय सरकार को अपने अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि ऐसा अंतिम निष्कर्ष जिस पर अभिहित प्राधिकारी पहुंचता है, नकारात्मक है, अर्थात् ऐसे प्रथमदृष्टया सत्य के प्रतिकूल है, जिसके आधार पर अन्वेषण शुरू किया गया था तो अभिहित प्राधिकारी अन्वेषण को तुरंत समाप्त कर देगा और केन्द्रीय सरकार संज्ञित पत्रकार को संग्रहण किया गया कोई अनतिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क वापस कर देगी।

(3) यदि अभिहित प्राधिकारी का अंतिम निष्कर्ष सकारात्मक है, अर्थात् ऐसे प्रथमदृष्टया सत्य की पुष्टि करता है, जिसके आधार पर अन्वेषण शुरू किया गया था तो केन्द्रीय सरकार यथास्थिति, शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की ऐसी रकम अवधारित करेगी जो प्राकलित बाउंटी या सहायकी की रकम से अधिक नहीं होगी।

19. शुल्क का अधिरोपण और संग्रहण :—केन्द्रीय सरकार, नियम 20 के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन से छह मास के भीतर, अंतिम निष्कर्ष के अंतर्गत आने वाली वस्तु के भारत में आयात पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित कर सकेगी जो शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की ऐसी रकम के बराबर होगी जिसे नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) इस प्रकार अधिरोपित कोई शुल्क या अतिरिक्त शुल्क अवधारण नियम 13 और उपनियम (1) के अधीन अधिरोपित कोई अनतिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क गैरपञ्चासपूर्ण आधार पर होगा और ऐसी वस्तु के सभी आयातों को लागू होगा, यदि वे बाउंटी वस्तु या सहायता प्राप्त हैं, और जहां लागू हो, क्षति पहुंचाने हैं सिवाय उन आंतों में आयातों की दशा में, जिनसे नियम 14 के उपनियम (2) के निवन्धनों के अनुसार वचनबद्ध प्रतिगृहीत किए गए हैं।

20. लोक सूचना :—यथास्थिति प्राधिकारी निम्नलिखित से संबंधित सभी आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित कराएगा :—

- (क) शुरू किया जाना,
- (ख) अन्वेषणों का निलम्बित या समाप्त,
- (ग) ऐसे मामलों में प्रारंभिक निष्कर्ष जिनमें अनतिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के अधिरोपित किए जाने की प्रस्थापना है; और
- (घ) अंतिम निष्कर्ष।

21. प्राकलित और अंतिम रूप में निर्धारित शुल्क के निशेष के बीच अंतर का उपचार :—(1) यदि अभिहित प्राधिकारी द्वारा किए गए अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित शुल्क या अतिरिक्त शुल्क पहले ही अधिरोपित और संगृहीत अनतिम शुल्क से उच्चतर है तो अंतर का आयातकर्ता से संग्रहण नहीं किया जाएगा।

(2) यदि अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् निर्यात शुल्क या अतिरिक्त शुल्क पहले ही अधिरोपित या संगृहीत अनतिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क से निम्नतर है तो अंतर को आयातकर्ता को वापस किया जाएगा।

22. पुनरीक्षण :—अभिहित प्राधिकारी, समय-समय पर, यथास्थिति, शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के निरंतर अधिरोपित की आवश्यकता का पुनरीक्षण करेगा और यदि उनका अपने को प्राप्त ऐसी जानकारी के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के निरंतर अधिरोपण के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है तो, केन्द्रीय सरकार को, उसके वापस लिए जाने की, सिफारिश करेगा।

[मि. सं. नं. 528/74/82-सीमा शुल्क (टी. यू.) (I)]

र. स. सिद्ध, अवरसचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 1985

No. 286/85-CUSTOMS

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 and Sub-section (3) of Section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Bounty-fed Articles and for Determination of Injury) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. Definition.— In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) "Act" means the Customs Tariff Act, 1975;
- (b) "designated authority" means the person appointed as designated authority under rule 3;
- (c) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture or production of the same or like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the allegedly bounty-fed or subsidised article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry :

Provided that in circumstances referred to in sub-rule (3) to rule 17 of these rules, the territory of a signatory may, in relation to the article in question, be divided into two or more competitive markets and the products within each of such market shall be regarded as a separate industry if—

- (i) the producers within such market sell all or almost all of their production of the article in question in that market; and
- (ii) the demand in the market is not in any substantial degree supplied by producers of the article in question located elsewhere in the territory;
- (d) "GATT Agreement on Subsidies and Countervailing Measures" means the Agreement on interpretation and Application of Articles VI, XVI and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade dated 12th April, 1979;
- (e) "interested party" means a party who is economically affected and is interested in the investigation under these rules;
- (f) "interested signatory" means a signatory who is economically affected and is interested in the investigation under these rules;
- (g) "signatory" means a country or territory which is a party to or has acceded to the Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI, and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade;
- (h) words and expressions used in these rules, but not defined, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Appointment of designated authority.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint the Secretary to the

Government of India in the Department of Commerce, in the Ministry of Commerce or such other person as that Government may think fit, as the designated authority for purpose of these rules.

(2) The Central Government may provide to the designated authority the services of such other persons and such other facilities as it deems fit.

4. Duties of the designated authority.—(1) It shall be the duty of the designated authority in accordance with these rules—

- (a) to investigate as to the existence, degree and effect of the alleged bounty or subsidy of any article.
- (b) to identify the articles liable for any duty or additional duty; and
- (c) to submit its findings to the Central Government as to the nature and amount of subsidy or bounty in relation to such articles.

(2) If the designated authority arrives at a finding after conducting investigation in accordance with the provisions of these rules that any country or territory has paid or bestowed directly or indirectly, any bounty or subsidy on any article to which sub-section (1) of section 9 of the Act applies, it may recommend to the Central Government, provisionally or otherwise the imposition of a duty, or as the case may be, an additional duty to the extent and in the manner provided in the said sub-section :

Provided that, in the case of countries or territories which have been notified in the Official Gazette under section 9B of the Act, no such duty or additional duty, as the case may be, shall be imposed unless the designated authority has given a further finding in accordance with these rules, that import into India of such articles causes or threatens to cause material injury to any industry established in India or material injury retards the establishment of any industry in India.

5. Decision as to Country of origin.—In cases where articles are not imported directly from the country of origin but are imported from an intermediate country, the provisions of these rules shall be fully applicable and any such transaction shall, for the purpose of the GATT Agreement on Subsidies and Countervailing Measures be regarded as having taken place between the country of origin and the country of importation.

6. Initiation of Investigation:—(1) The designated authority shall normally initiate an investigation only upon receipt of a written request by or on behalf of the affected domestic industry;

(2) Before initiating an investigation, the designated authority shall satisfy itself that it has sufficient prima facie evidence of—

- (a) The existence of bounty or subsidy and the quantum thereof;
- (b) injury, where applicable, to the extent referred to in Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade as Interpreted in the GATT Agreement on subsidies and Countervailing Measures; and

(c) where applicable, a causal link between such imports and the alleged injury.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may initiate an investigation suo moto, if it is satisfied from information received from the Collector of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source, that sufficient prima facie evidence exists as to the existence of bounty or subsidy and, where applicable, injury.

7. Notification of investigation.—The designated authority shall, after deciding to initiate an investigation, communicate to the governments of the exporting countries concerned names of the articles which are proposed to be subjected to such investigation.

8. Opportunity to inspect, represent.—The designated authority shall allow the duly authorised representatives of interested parties and interested signatories—

- (a) upon their request, a reasonable opportunity to inspect any relevant information that is used by it in the investigation that is not confidential; and
- (b) an opportunity to represent their views in writing, and on sufficient cause shown, orally.

9. Confidential information.—(1) Any information provided to the designated authority on confidential basis by any party in the course of an investigation shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed by the designated authority to any other party without the specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties submitting information on confidential basis to furnish non-confidential summaries thereof and if, in the opinion of a party, such information is not susceptible of summary, such party shall provide to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not willing to disclose the reasons, it may be open to the designated authority to disregard such information.

10. Investigation in the territory of other signatories.—(1) The designated authority may carry out investigation in the territories of other signatories if the circumstances of a case warrant, provided that the designated authority notifies such signatories in advance and such signatories do not object to the investigation.

(2) The designated authority may also carry out investigations at the premises of any commercial organisation and may examine its records if such organisation agrees and if the signatory in whose territory the said commercial organisation is situated, is notified and has not raised any objection for the conduct of such investigation.

11. Finding on the basis of best information.—In a case in which an interested party or a signatory refuses access to, or otherwise does not provide necessary information to the designated authority within a reasonable period or impedes its investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the information available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under the circumstances.

12. Preliminary findings.—The designated authority shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and shall, in appropriate cases, record a preliminary finding.

13. Provisional duty.—The Central Government may impose at any time, provisional duty or additional duty, as the case may be, on an article if the designated authority makes, on the basis of best information available to it, a preliminary finding that a bounty or subsidy is being provided in respect of the articles which are the subject matter of the investigation :

Provided that in the case of an investigation to which section 9B of the Act applies, no provisional duty or additional duty as the case may be, shall be imposed unless the designated authority arrives at a further finding on the basis of best information available to it that there is sufficient evidence of the import of such article causing or threatening to cause material injury to any industry established in India or materially retarding the establishment of any industry in India within the meaning of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade as interpreted by the GATT Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and that the provisional duty is necessary to prevent injury being caused during the period of investigation :

Provided further that no such provisional duty shall exceed the provisionally estimated amount of bounty or subsidy.

14. Termination or suspension of investigation.—

1. The designated authority may, at its discretion, suspend or terminate an investigation—

- (a) on receipt of a request in writing for doing so on behalf of the domestic industry affected at whose instance the investigation was initiated; or
- (b) when, in the course of an investigation, the designated authority is satisfied that there is not sufficient evidence of bounties or subsidies, or where applicable, injury, to justify continuation of the investigation.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may suspend or terminate an investigation if—

- (a) the government of the exporting signatory—
- (i) gives an undertaking in writing to the effect that it would withdraw the bounty or subsidy; or

- (ii) in the case of countries to which section 9B of the Act applies undertakes to limit the quantum of bounty or subsidy within reasonable limits, or to take other suitable measures to neutralise the effect of such bounty or subsidy provided that the designated authority is satisfied that the injurious effect of the subsidy is eliminated; or
- (b) the exporters concerned agree to revise their prices in case of countries to which section 9B of the Act applies; and the designated authority is satisfied that the injurious effect of the subsidy is eliminated :

Provided that increase in prices as a result of clause (b) shall not be higher than what is necessary to eliminate the amount of bounty or subsidy.

(3) No undertaking as regards price increase under clause (b) sub-rule (2) shall be accepted from foreign exporters unless the designated authority has after initiating an investigation in accordance with the provisions of these rules, obtained the consent of the government of the exporting signatory for such revision :

Provided that no such undertaking offered by the foreign exporters shall be accepted by the designated authority if it considers their acceptance thereof as impracticable or as unacceptable for any other reason.

(4) Where the designated authority has accepted any, undertaking under clause (b) of sub-rule (2), it may request any signatory or exporter from whom such undertaking has been accepted, to provide from time to time, information relevant to the fulfilment of the undertaking and to permit verification of relevant data :

Provided that in the case of any violation of any of the undertakings, the designated authority may impose provisional duty or additional duty, as the case may be, on the basis of best information available to it.

(5) The designated authority shall, suo moto or on the basis of any request received from the exporters or importers of the article in question or any other interested person review at any time the need for the continuance of any undertaking given earlier.

15. Final finding.—The designated authority shall, within one year from the date of initiation of an investigation or within such extended time as the Central Government may grant in exceptional cases, give a final finding as to whether or not—

- (a) bounty or subsidy is being granted in respect of the article under investigation and the quantum of such bounty or subsidy, and
- (b) in the case of countries to which section 9B of the Act applies, whether imports of such articles into India causes or threatens to

cause material injury to any industry established in India or materially retards the establishment of any industry in India.

16. Determination of bounty or subsidy.—Any exemption of an exported article from duties or taxes borne by a like product when destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in amounts not in excess of those which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy for purposes of these rules and the term 'subsidy' shall include, but is not limited to any subsidy described as such in the Annexure to the GATT Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

17. Determination of injury.—(1) In the case of countries or territories notified under sub-section (2) of section 9B of the Act, a duty or additional duty as the case may be, shall not be imposed under section 9B of the act, unless the designated authority gives a further finding that the import of such article into India causes or threatens to cause material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India.

(2) When a finding of injury is made under sub-rule (3), such finding shall involve an examination of the facts which the designated authority considers relevant under the circumstances including the volume of bounty-fed or subsidised imports and their effect on prices in the domestic market for like products and the consequent impact or such imports on domestic producers of such products.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if—

- (i) there is a concentration of bounty-fed or subsidised imports into an isolated market and
- (ii) the bounty-fed or subsidised imports are causing injury to the producers of all almost all of the production within such market.

18. Result of final finding.—(1) The designated authority shall, on completion of its investigation submit to the Central Government its final findings;

(2) If the final finding arrived at by the designated authority is negative, that is, contrary to the prima facie evidence on whose basis investigation was initiated, the designated authority shall terminate investigation forthwith and the Central Government shall refund any provisional duty or additional duty collected, to the party concerned.

(3) If the final finding of the designated authority is in the affirmative, that is, confirming the prima facie evidence on whose basis investigation was initiated, the Central Government shall determine the amount of duty or additional duty, as the case may be, not exceeding the amount of estimated bounty or subsidy.

19. Imposition and collection of duty.—(1) The Central Government may, within six months of the publication of the final findings, by the designated authority under rule 20, impose, by notification in the Official Gazette, upon importation into India of the article covered under the final finding, a duty or additional duty, as the case may be, equal to the amount of duty or additional duty as determined by the Central Government under clause (3) of rule 18.

(2) Any duty or additional duty so imposed or a provisional duty or additional duty imposed under rule 13 and sub-rule (1) shall be on a non-discriminatory basis and applicable to all imports of such article, if found to be bounty-fed or subsidised and where applicable, causing injury except in the case of imports from those sources from which undertakings in terms sub-rule (2) of rule 14 have been accepted.

20. Public notice.—The designated authority shall cause to be published in the Official Gazette, all orders relevant to—

- (a) initiation,
- (b) suspension or termination of investigations,
- (c) preliminary findings in cases where provisional duty or additional duty is proposed to be imposed, and

(d) final findings.

21. Treatment of difference between deposit of estimated and finally assessed duty.—(1) If the duty or additional duty imposed by the Central Government on the basis of the final findings of the investigation conducted by the designated authority is higher than the provisional duty already imposed and collected, the differential shall not be collected from the importer.

(2) If the duty or additional duty fixed after the conclusion of the investigation is lower than the provisional duty or additional duty already imposed and collected, the differential shall be refunded to the importer.

22. Review.—The designated authority shall, from time to time, review the need for continued imposition of the duty or additional duty, as the case may be, and shall, if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty or additional duty, recommend to the Central Government for its withdrawal.

{F. No. 528/74/82-Cus(TU)(I)}

R. S. SIDHU, Under Secy.